(a) whether there are any complaints about disbursement of loans by Directorate of Industries, Delhi;

(b) the number of applications for loan for industrial purpose pending with the Directorate during the last three years; and

(c) the number of registered societies who applied for industrial loan but have not received loans since March, 1979 to March, 1981?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) No, Sir.

(b) and (c). Under Block Loan Scheme two cases are pending for want of requisite recommendation of the Registrar of Cooperative Societies, Delhi and execution of legal documents respectively. Under the KVI Scheme, three cases were rejected during the period from March, 1979 to March, 1981 as the parties concerned did not comply with the stipulated conditions or they failed to furnish the requisite documents.

Police Assistance sought by Jawaharlal Nehru University

7569. SHRI INDRAJIT GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Delhi Police assistance was sought recently by the authorities of Jawaharlal Nehru University to prevent unlawfully entry into the Campus and undesirable activities therein of one Rajbir Singh Hooda, a non-student and well-known anti-social element;

(b) if so, whether police took no action in the matter and the reasons therefor; and

(c) whether complaints against Hooda were also received from some students' organisations and if so, the nature thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b). On 9-3-1981, Jawaharlal Nehru University had sent to the police a cyclostyled letter intimating that the University Campus was out of bounds for Shri Rajbir Singh Hooda. Subsequently, on receipt of a letter dated, 13-3-1981 from the Vice-Chancellor, Jawaharlal Nehru University, intimating that Shri Rajbir Singh Hooda was reported to have been seen in the campus, a case FIR No. 68 dated 13-3-1981 u/s 448 IPC, Police Station Vasant Vihar was registered. Shri Hooda was arrested and later bailed out. Preventive proceedings have also been initiated against Shri Hooda u/s 107/150 Cr. P. C. and the same is pending trial in the Court of Assistant Commissioner of Police, Delhi Cantt.

(c) No complaint has been received by the local police from any students organisations against Shri Rajbir Singh Hooda. However, on the complaint of one Shri Shailender Yadav, resident of 73, Jubilee Hall, a case FIR No 127, dated 27-2-1981 u/s 324 IPC has been registered at Police Station Roshan Ara.

हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

7570. श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में हिमाचल प्रदेश में किन-किन उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव है ;

(ख) राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में किन-किन उद्योगों की स्थापना के लिए सिफारिश की है; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के बारे में सरकार की क्या नीति है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सरकारी क्षेत्र की केन्द्रीय परियोजनाओं के स्थापना-स्थल तकनीकी-आर्थिक कारणों पर आधारित होते हैं । किन्तु, संयुक्त क्षेत्र के कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने छठी पंचवर्षीय योजना 1981–85 के दौरान क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित उद्योगों का पता लगाया है ।

(1) चमड़ा चमकाने वाले रसायन (लैदर फिनिशिंग केमिकल्स) ।
(2) आटो-मोबाइल ग्लास बोतल संयंत्र ।
(3) औद्योगिक सिलाई की सुइयां ।
(4) औद्योगिक अल्कोहल ।
(5) काटन-सिन्थेटिक एकक ।
(6) सिलिकन कार्बाइड ।
(7) सिरेमिक केपासिटर/परियोजना ।
(8) डाई कम्पलैक्स ।
(9) टेक्सटाइल कम्पलैक्स ।
(10) सीमेंट संयंत्र ।

राज्य में उद्योगों के संवर्द्धन के लिए राज्य सरकार के पास भी राज्य वित्त निगम और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास जैसी योजनाएं हैं ।

सामान्यत: सरकारी क्षेत्र में लघु एककों की स्थापना नहीं की जाती है । किन्तु, निजी क्षेत्र में इस प्रकार के उद्योगों के संवर्द्धन के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, सहायता और प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं । वर्ष 1980–85 की छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1984–85 के अन्त तक राज्य में ऐसे 8800 लघु एककों की स्थापना की परिकल्पना की है ।

क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए समय-समय पर अनेक रियायतों और सुविधाओं की घोषणा की है । इनमें रियायती वित्त, कम ब्याज की दर पर सीड/मार्जिन धनराशि स्थाई पूंजी-निवेश पर संघी राजसहायता, परिवहन राजसहायता (केवल पहाड़ी क्षेत्रों में) आय-कर में छूट आदि शामिल हैं ।

इसके अलावा लघु एककों के लिए परामर्शदायी सेवायें, ब्याज रहित सहायता मशीनों कच्चे माल एवं उपकरणों आदि में आयात की विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

Posting of Military Officers in Ministry of Defence

7571. SHRI ERA ANBARASU: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the reasons why officers from the Army, Navy and Air Force are not posted in the Ministry of Defence in place of senior IAS officers;

(b) the reasons why large number of civilian staff are employed in Defence establishments; and

(c) the reasons why these civilian personnel are not replaced by regular serving personnel and ex-servicemen?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE